Forums. The break-up of the number of cases instituted and disposed of during pending in the Delhi Consumer Redressal the last three years is as follows :—

Year	No. of Cases		
	Instituted	Disposed of	Pending
1990	2250	1611	1491 Includes backlog
1991	2455	1798	2148 of pending cases of
1992	5778	2517	4408 previous years from 1988 onwards

(e) Two District Forums are already functioning in Delhi. Delhi Government proposed to set up a third District Forum to facilitate the speedy disposal of consumer cases. As a remedial step, additional staff has also been deputed by the Delhi Administration from time to time in addition to existing staff so as to ensure speedy disposal of cases.

राज्यों में खाद्य तेल का वितरण

2283. **श्रीमती चन्द्रिका अग्निमन्त्र जैन** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** 6 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अंतारांकित प्रश्न 347 के लिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की कुल मांग, विशेष तौर से गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में कितनी है और आयातित खाद्य तेल के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य तेल की सप्लाई के संबंध में प्रति इकाई और प्रति कार्ड अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार किया है; और

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान खाद्य तेल की उचित दर की दुकानों के लिए सरकार खाद्य तेल की कितनी मात्रा खरीदने का विचार रखती है, और प्रत्येक उपभोक्ता को प्रति कार्ड तेल की कितनी मात्रा दी जायेगी तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) गुजरात सरकार ने सितम्बर तथा अक्तूबर, 1993 के लिए प्रतिमाह पामोलीन की 4000 मी. टन मात्रा की मांग की है। इसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1993 के महीनों के लिए प्रतिमाह 10,000 मी. टन पामोलीन आवंटित करने के लिए कहा। पामोलीन के सीमित मात्रा में आयात किए जाने के कारण गुजरात को अक्तूबर, 1993 के महीने के लिए 2000 मी. टन तथा दिसम्बर, 1993 के महीने के लिए 2550 मी. टन पामोलीन आवंटित किया गया है। महाराष्ट्र को अक्तूबर, 1993 के लिए 2,600 मी. टन पामोलीन आवंटित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने नवम्बर, 1993 में सूचित किया था कि उन्हें कोई पामोलीन का कोई आवंटन न किया जाए, क्योंकि त्यौहार मौसम समाप्त हो चुका है।

(ख) देशीय खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि को देखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए आयातित खाद्य तेल नियमित आधार पर आवंटित नहीं किया जाता है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य तेल के वितरण के लिए प्रति यूनिट/कार्ड पर अधिकतम सीमा नियत करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसके अलावा, राज्य के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण करने, जिसमें, वितरण

की मात्रा नियत करना आदि शामिल है. की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए देशीय खाद्य तेलों की अविप्राप्ति करने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्य तेल की मांग व आपूर्ति की स्थिति पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाता है और यदि इन दोनों के बीच कोई अंतर हो तो उसकी पूर्ति यथा-संभव सीमा तक आयात करके की जाती है।

IMPORT OF EDIBLE OIL

2284. SHRI G. G. SWELL : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to import 30,000 tons of edible oil at a cost of Rs. 45 crores ; and

(b) how does Government justify this when it is known that the National Dairy Development Board was holding a stockpile of 1.27 lakh tonnes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) In order to keep the prices of edible oils undercheck, the Government has imported 30,000 MTs. at a price of about Rs. 37 crores and 12,000 M.Ts. at a price of about Rs. 14 crores. These imports were intended to supplement the availability of edible oils in the country around the festival season when the demand for edible oils was much higher. When the decision to import the first consignment of 30,000 MTs. of edible oil was taken in early September, 1993, National Dairy Development Board did not have a stock of 1.27 lakh tonnes of edible oils.

DETAILS OF WOMEN CO-OPERATIVES ENGAGED AS TRADERS AND SUPPLIERS FOR SUPER BAZAR

2285. SHRI DILIP SINGH JUDEV : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) the number of women co-operatives and Widow Welfare Associations which are registered with Super Bazar as suppliers and trading agents ;

(b) whether there is any provision to give priority to these Associations to supply poducts and encourage them to create self-income sources ;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) Super Bazar has informed that Four Women Co-operative societies are registered. No Widow Welfare Association is, however, registered with them.

(b) Yes, Sir.

(c) Super Bazar has reported that they display their products properly, give them repeat orders quickly before their stocks get exhausted and advise them to fix competitive prices. Priority is also given in releasing their payments.

(d) Does not arise.

ALLOCATION OF ADDITIONAL QUOTA OF PALMOLEIN TO SAURASHTA

2286. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to allocate additional quota of Palmolein to